न्यूज़ इनबॉक्स

सरकार सुधारेगी एयर इंडिया की हालत

नई दिल्ली| सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह संकटग्रस्त एयर इंडिया की हालत सुधारने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी, जिसमें इस सरकारी कंपनी के खर्चों में कटौती करते हुए नकदी प्रवाह बढ़ाना शामिल है। इसी तरह घाटे वाले मार्गों पर एयर इंडिया की उड़ानें बंद करने की योजना भी है। नागर विमानन मंत्री वायलार रवि ने यह जानकारी दी। अगले प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में एक कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को संकट से निकालने के लिए खर्चों में कटौती करने तथा इसे नकदी प्रवाह बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से अव्यवहारिक मार्गों पर परिचालन बंद कर, मुनाफे वाले रूटों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सब फिलहाल प्रस्ताव के रूप में है और कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने खर्च में कटौती के तहत एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या में किसी तरह की कटौती की संभावना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को संकट से उबारने में राज्यों की मदद की जरूरत भी है। नागर विमानन मंत्रालय से बिक्री कर घटाने को कहा है कि ताकि इसे तेल की लागत कम हो। उन्होंने कंपनी के बारे में कैग की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी से इनकार किया। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया को बीते कई साल से लगातार भारी घाटा हो रहा है। रवि ने कहा कि पायलटों की हड़ताल ने कंपनी के लिए हालात और कठिन कर दिए हैं।

किंगफिशर जुटाएगी 2,000 करोड़ रुपए

मुंबई| विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने कहा कि वह राइट इश्यू के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिससे कंपनी को वित्तीय समस्या से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसके निदेशक मंडल ने राइट्स के आधार पर इक्विटी पूंजी जारी करने की अनुमति दे दी है, जो 2,000 करोड़ रुपए से अधिक न हो। निदेशक मंडल ने तीन जनवरी 2011 को जारी वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर की शर्तों में भी बदलाव किया है। नई शर्तों के मुताबिक कंपनी ने कहा कि ओसीडी धारक निदेशक मंडल द्वारा तय कीमत पर डिबेंचर को शेयर में तब्दील कर सकेंगे। कंपनी ने जनवरी में कुछ इकाइयों को 700 करोड़ रुपए का ओसीडी जारी किया था।

सेल के एफपीओ को लेकर अनिश्चितता

नई दिल्ली| सरकार ने कहा कि सरकारी कंपनी सेल के शेयरों की एक और सार्वजनिक पेशकश के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। सेल के शेयरों की एक और सार्वजनिक बिक्री का प्रस्ताव है पर इस निर्गम को बाजार में लाने का कार्यक्रम टलता जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं करने के बावजूद उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष में इस महारत्न कंपनी की दूसरी पेशकश (एफपीओ) आ जाएगी। इस्पात सचिव पीके मिश्रा ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के सम्मेलन में बताया कि यह काम उचित समय देख कर और जब शेयर बाजार की स्थिति ठीक हो, तब किया जाना चाहिए। अभी शेयर बाजार में अस्थिरता है। हम अब भी यह निर्गम चालू वित्त वर्ष के दौरान ही लाना चाहते हैं। सेल में सरकार की हिस्सेदारी 85 फीसदी से अधिक है। एफपीओ लाने की समयसीमा बाजार के मुश्किल हालात के अलावा कोयले की कीमत में बढ़ोतरी, मर्चेंट बैंकरों के साथ हुई समस्या जैसी कई वजहों से पिछले साल दिसंबर से टलती जा रही है। कंपनी का शेयर इस साल की शुरूआत से 43 फीसदी गिर चुका है। जुलाई में इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि इस्पात क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी का एफपीओ दिवाली के आसपास आ सकता है। इस निर्गम के जरिए सरकार सेल में अपनी और पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी जबकि कंपनी पांच प्रतिशत नए शेयर जारी करेगी।

विप्रो ने ग्रामीण बीपीओ सेंटर खोला

नई दिल्ली | विप्रो बीपीओ ने आज तमिलनाडु के मंजाकुड्डी गांव में अपना पहला ग्रामीण सेंटर खोला जिससे कि वह इस क्षेत्र में उपलब्ध साक्षर टैलेंट पूल का लाभ उठा सके। तमिलनाडु में मंजाकुड्डी सेंटर के पास 120 सीट की क्षमता है और यह रिटेल सेक्टर में एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट के लिए 50 सीट के पॉयलट प्रोजेक्ट के साथ खुलेगा। विप्रो ने एक बयान में कहा कि विप्रो की योजना तमिलनाडु में मार्च 2013 तक अपने ग्रामीण बीपीओ ऑपरेशंस को 500 सीट तक पहुंचा देगी और निकट भविष्य में इस बीपीओ मॉडल को अन्य राज्यों में भी दुहराएगी। विप्रो बीपीओ के सीनियर उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल हेड मनीष दुगर ने कहा कि रुरल बीपीओ एक बिजनेस लीडर के रूप में हमारे देश के विकास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

सेंसेक्स 16,000 से नीचे बंद

पिछले 18 महीनों में पहली बार इतना झुका शेयर बाजार

बिजनेस भास्कर/एजेंसियां | नई दिल्ली/मुंबई

पिछले कुछ समय के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चल रही उठापटक से हलकान भारतीय बाजार एक बार फिर अमेरिका से ही चली आशंका का शिकार बना। शुक्रवार को सप्ताह के कारोबार के आखिरी दिन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30-शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 297.50 अंक यानी 1.84 फीसदी गिरकर 15,848.83 अंक के स्तर पर आ गया। पिछले 18 महीनों के दौरान सेंसेक्स पहली बार 16,000 अंक के स्तर से नीचे आया है। अमेरिकी फेडरल ने अपने बयान अमेरिका सहित दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने के संकेत दिए हैं।

दिन के कारोबार में सभी 13-सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए। इनमें रियल्टी, मेटल, ऑयल एंड गैस तथा बैंकेक्स स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इनमें से कई स्टॉक्स पिछले 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर चले गए। सेंसेक्स पैक में सबसे ज्यादा 4.61 फीसदी की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के स्टॉक्स में रही। बाजार की कुल गिरावट में अकेले आरआईएल की हिस्सेदारी 75 अंक से ज्यादा की थी। इस गिरावट के बाद बाजार पूंजीकरण के लिहाज से आरआईएल ने एक बार फिर सबसे प्रतिष्ठित कंपनी होने का ताज गंवाया है। इस बार कंपनी से यह स्थान सार्वजनिक उपक्रम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने छीना है। आईटीसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक,कोल इंडिया, एचडीएफसी, एलएंडटी, ओएनजीसी तथा टाटा मोटर्स जैसे दिग्गजों की भी बाजार की कुल गिरावट में बड़ी भूमिका रही।

बीएसई-सेंसेक्स ने कारोबार की शुरुआत ऊंचे स्तर से की थी। कारोबार के कुछ ही समय में यह 110 अंक चढ़कर 16,256.38 अंक के स्तर तक भी गया। लेकिन, बढ़त बनाए रखने में नाकामयाब बाजार कारोबार के आखिर में 16,000 अंक के स्तर से नीचे बंद हुआ। इससे पहले, 5 फरवरी, 2010 को बाजार 15,790.93 अंक के स्तर पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50-शेयरों वाले निफ्टी में भी शुक्रवार को 91.80 अंक यानी 1.90 फीसदी गिरावट आई। इस गिरावट के बाद कारोबार के आखिर में यह भी 4,747.80 अंक के साथ पिछले 18 महीनों के सबसे निचले स्तर पर चला गया।

ब्रोकरों ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बेन बर्नांक के बयान में अमेरिका समेत दुनियाभर के दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं में मंदी रहने के संकेत के चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली कर खुद को सुरक्षित कर लेने में ही भलाई समझी। इस बारे में मोतीलाल ओसवाल सिक्युरिटीज के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट पराग डॉक्टर ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान भारतीय बाजार के कारोबार में अमेरिकी सरकार द्वारा क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) पैकेज देने तथा यूरो जोन के कर्ज संकट के समाधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का दूर होते जाना भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

ओएनजीसी पहले और रिलायंस दूसरे नंबर पर

बाजार पूंजीकरण में कोल इंडिया तीसरे नं. पर

एजेंसी | मुंबई

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी शुक्रवार को देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, जबकि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे पायदान पर पहुंच गई। करीब साढ़े चार साल के अंतराल के बाद ओएनजीसी फिर से अव्वल कंपनी बन गई और उसका बाजार पूंजीकरण 2,37,842 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि आरआईएल का बाजार पूंजीकरण 2,35,571 करोड़ रुपए रहा।

हालांकि, ओएनजीसी का बाजार पूंजीकरण आरआईएल के बाजार पूंजीकरण से महज करीब एक प्रतिशत ही अधिक है और अगले सप्ताह शेयर बाजार में दोबारा कारोबार शुरू होने पर सबकी नजर ओएनजीसी के शेयर पर होगी। आरआईएल ने पहली बार 2006 के अंत में ओएनजीसी को पहले पायदान से हटाकर अव्वल कंपनी बनने का रुतबा हासिल किया था। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी ने फिर से नंबर एक का स्थान हासिल कर लिया, लेकिन वह कुछ समय तक ही इस पर काबिज रह सकी। अगर पिछले कुछ दिनों को छोड़ दें तो फरवरी, 2007 से रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर एक के पायदान पर काबिज है। इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया ने 17 अगस्त को आरआईएल को पहले पायदान की कुर्सी से उतार कर खुद काबिज हो गई थी।

बाजार में गिरावट के बीच ओएनजीसी का शेयर आज 4.20 रुपए टूटकर 278 रुपए पर बंद हुआ जबकि रिलायंस 34.80 रुपए की गिरावट के साथ 719.50 पर आ गया। कोल इंडिया का शेयर भी 14.60 रुपए नीचे आकर 359.75 पर पहुंच गया।

सरकार जल्द देगी एसबीआई पूंजी समावेश को मंजूरी

नई दिल्ली| सरकार के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजी समर्थन मुहैया करा देने की उम्मीद है। इस बारे में जल्द ही फैसला कर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हम एसबीआई में पर्याप्त रूप में पूंजी समावेश करेंगे जिससे कि टियर-1 पूंजी आठ फीसदी से ऊपर बनी रहे जैसी कि सरकार की योजना है।

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने कुछ सप्ताह पहले इस बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त किया था। इसकी जांच की जा रही है और इसके बारे में जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, एसबीआई को अगले दो वित्त वर्ष के दौरान अपनी विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव के आधार पर पूंजी समावेश के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। यह राइट्स इश्यू, प्रेफेरेंसियल शेयर इश्यू जैसे माध्यमों के जरिये किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पूंजी समावेश के लिए सटीक तंत्र पर टिप्पणी करना अभी काफी जल्दीबाजी होगी क्योंकि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

जून 2011 तक एसबीआई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.6 फीसदी रहा।

1,21,000 करोड़ का तेल कंपनियों को नुकसान

एजेंसी | नई दिल्ली

तेल मंत्री जयपाल रेड्डी ने कहा कीमतों में वृद्धि के बावजूद हो रहा नुकसान

सरकारी तेल कंपनियों को नियंत्रित दर पर डीजल, घरेलू एलपीजी और केरोसिन की बिक्री के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,21,000 करोड़ रु पए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। यह बात आज तेल मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने कही।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती के अलावा डीजल की कीमत तीन रु पए, केरोसिन दो रु पए प्रति लीटर और एलपीजी की कीमत 50 प्रति सिलेंडर बढ़ाने के बावजूद तेल कंपनियों को यह घाटा हो सकता है। तकनीकी भाषा में यह तेल कंपनियों की कम वसूली यानी 'अंडर-रिकवरी' है। रेड्डी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय परामर्श समिति की बैठक में कहा, 'इन पहलों के बावजूद तेल विपणन कंपनियों को फिलहाल 235 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आधार पर नुकसान उठाना पड़ रहा है और आशंका है कि 2011-12 में 1,21,000 करोड़ रु पए का नुकसान होगा।'कीमतों में बढ़ोतरी और सीमाशुल्क को पांच फीसद से घटाकर शून्य पर लाने और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2.60 रुपए प्रति लीटर घटाने से पहले सरकारी तेल कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में 1,71,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका थी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को फिलहाल डीजल पर 4.97 रुपए प्रति लीटर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले केरोसिन पर 23.74 रु पए प्रति लीटर और घरेलू गैस पर 247 रु पए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है।

वीआईपी में प्रमोटरों का खेल भी वीआईपी!

बिजनेस भास्कर | मुंबई

कबूलनामा

कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल ने बिजनेस भास्कर को बताया कि प्रमोटरों की हिस्सेदारी की जानकारी देने में असावधानीवश गलती हो गई। उन्होंने बिजनेस भास्कर को भेजे पत्र में सभी नए प्रमोटरों की जानकारी देते हुए कहा है कि जिस समय उन कंपनियों ने अपने शेयर बेचे या खरीदे, उस समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए वे प्रमोटरों की हिस्सेदारी में शामिल नहीं हो पाई।

वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर पूंजी बाजार नियामक संस्था सेबी की जांच की जद में आ गए हैं। सेबी को अंदेशा है कि उसे अंधेरे में रखकर वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटरों द्वारा हिस्सेदारी की गैरकानूनी रूप से खरीद-फरोख्त की गई है। सेबी का कहना है कि वह इस मामले में कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

मामला यह है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज ने अभी तक कंपनी में अपने प्रमोटरों की हिस्सेदारी 40-45 फीसदी के बीच सेबी को बताई है। जून, 2011 में भी उसने यही कहा कि उसकी कंपनी में कुल पांच प्रमोटर हैं, जिनके पास 44.12 फीसदी हिस्सेदारी है। लेकिन सेबी द्वारा की गई जांच में पता चला कि कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 51.98 फीसदी है। सेबी की इस जांच के बीच ही वीआईपी प्रमोटरों ने इस महीने की 10 तारीख को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरधारिता पैटर्न में इसकी जानकारी दे दी। इसके अगले ही दिन 11 अगस्त को कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मनोज तुलसियान ने इस्तीफा दे दिया। कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल ने बिजनेस भास्कर को बताया कि प्रमोटरों की हिस्सेदारी की जानकारी देने में असावधानीवश गलती हो गई। उन्होंने बिजनेस भास्कर को भेजे पत्र में सभी नए प्रमोटरों की जानकारी देते हुए कहा है कि जिस समय उन कंपनियों ने अपने शेयर बेचे या खरीदे, उस समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए वे प्रमोटरों की हिस्सेदारी में शामिल नहीं हो पाई। पर बाजार के जानकार कहते हैं कि यह मामला 2004 से चल रहा है और पिछले 7 सालों में कंपनी को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, जो शक पैदा करता है। आश्चर्य की बात यह है कि नए प्रमोटरों में जो हिस्सेदारी बढ़ाई गई है उसमें खुद चेयरमैन दिलीप पिरामल और उनकी पत्नी भी हैं।

सीएंडसी की आय में 10 % इजाफा

नई दिल्ली | इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स ने 30 जून, 2011 को खत्म वित्त वर्ष के दौरान 1,290 करोड़ रुपये की कुल आय हासिल की। पिछले वित्त-वर्ष की समान अवधि के मुकाबले यह 10 फीसदी अधिक है। पिछले वर्ष कंपनी की कुल आय 1,168 करोड़ रुपये रही थी। सी एंड सी कंस्ट्रक्शन के निदेशक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में आलोच्य अवधि का परिणाम घोषित किया गया। इसके बाद बिजनेस भास्कर से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष गुरजीत सिंह जोहर ने बताया कि यूं तो बीते वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए कठिन वर्ष साबित हुआ। इसके बावजूद कंपनी की कुल आय में उम्मीद से अधिक की वृद्धि हुई।

शादी का सीजन, ऑफर ही ऑफर

बिजनेस भास्कर | मुंबई

रिटेलर अब शादी ब्याह के लिए नए ऑफर लेकर आ रहे हैं। कई नए और अनोखे प्रकार के ऑफर इन दिनों बाजार में दिखाई दे रहे हैं। इनमें डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, गहनों, हनीमून पैकेज और फोटोग्राफ व वीडियो फिल्म के लिए कई ऑफर हैं। मुंबई में कई फैशन डिजाइनरों की रिटेलरों के साथ करार कर अपने वेडिंग कलेक्शन बाजार में पेश करने की योजना है जिससे ग्राहक आसानी से वेडिंग कलेक्शन की खरीदारी कर सकें। आदित्य बिरला नूवो ब्रांड के तहत लाइफ क्लब फैब्रिक लाइफस्टाइल गुरू रोहित बाल पेश कर रहे हैं।

लेकिन इस बार वेडिंग कलेक्शन के अलावा, ज्वैलर्स द्वारा गहनों के साथ सोने के सिक्के खरीदने की स्कीम शादी ब्याह के लिए दी जा रही हैं। बाम्बे बुलियन एसोसिएशन ने बिजनेस भास्कर को बताया कि सोने के चढ़े भाव की वजह से ज्वैलर्स शादी ब्याह में सोने के गहनों के साथ सोने के सिक्के खरीदने का भी ऑफर दे रहे हैं। उनकी राय है कि दुल्हा-दुल्हन को गहनों के बजाए सिक्के देना निवेश के रूप में भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके साथ ही, गोल्ड ईटीएफ भी उपहार के रूप में दिए जाने का चलन बढ़ रहा है। यह शुरूआत फिलहाल केवल महानगरों में दिखाई दे रही है। तनिष्क ने इस अवसर पर तमन्ना सेविंग स्कीम शुरू की है।

कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिडेट ग्राहकों को शादी ब्याह की फोटोग्राफी के लिए सेवा प्रदान कर रही है। कंपनी अपनी यह सेवा सीधे ग्राहक को नहीं देती बल्कि कोडक एक्सप्रेस स्टोर के जरिए ग्राहक इसकी सुविधा उठा सकते हैं। इसमें कुछ पैकेज भी दिए जाते हैं। ग्राहक कोडक डॉट वेडिंगसूत्रा डॉटकॉम पर जाकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाम्बे स्टोर स्टोर ने वेडिंग कलेक्शन में डिजाइनर बैग की रेंज पेश की है जिसमें मेकअप, टैवल और हैंड बैग शामिल हैं।

अभिभावकों का क्लेम बीमा कंपनियों के लिए महंगा पड़ रहा

नई दिल्ली| ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए कर्मचारियों की तुलना में उनके अभिभावकों का क्लेम चुकाना महंगा पड़ रहा है। ऐसे में कई बीमा कंपनियां कर्मचारियों के अभिभावकों के क्लेम की राशि को सीमित करने का कदम उठाने के अलावा कर्मचारियों से मेडिकल बिल साझा करने को कह रही हैं। बीमा कंपनियों के मुताबिक, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर से आने वाले कुल क्लेम में कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों के अभिभावकों से है। फ्यूचर जेनेराली के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमुख शीराज देशपांडे का कहना है कि अभिभावकों का क्लेम अधिक होने के कारण बहुत सी कंपनियां ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में अभिभावकों को अलग से कवर करने के लिए कह रही हैं। इसके अलावा, हम कॉरपोरेट कंपनियों को यह विकल्प भी दे रहे हैं कि कर्मचारी अभिभावकों के क्लेम की राशि का एक हिस्सा साझा करें। इन दिनों अधिकतर बीमा कंपनियां ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कर्मचारी और तीन आश्रितों तक को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मुहैया कर रही हैं।

पुराने गोल्ड लोन पर पा सकते हैं ज्यादा लोन

बिजनेस भास्कर | नई दिल्ली

फायदे का कर्ज

बढ़ी हुई कीमत पर अतिरिक्त कर्ज प्राप्त कर सकते हैं ग्राहक

अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले ग्राहकों को सुविधा दे रही हैं कंपनियां

यदि आपने गोल्ड लोन ले रखा है, तो उसी गिरवी रखे सोने पर आप ज्यादा कर्ज हासिल कर सकते हैं। देश की प्रमुख गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां अपने बेहतर रिकार्ड रखने वाले ग्राहकों को सोने की बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से ज्यादा कर्ज ऑफर कर रही हैं। कंपनियों के अनुसार यह सुविधा वह उन्हीं ग्राहकों को दे रही हैं, जिनका कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड अच्छा है। इसके जरिए ग्राहक न केवल अपने गिरवी रखे उसी सोने पर ज्यादा कर्ज पा सकते हैं, बल्कि कंपनियों को कारोबार के हिसाब से भी उन्हें ज्यादा आय होगी।

पिछले एक साल में सोने की कीमत में 9,000-10,000 रुपये तक प्रति दस ग्राम पर इजाफा हो चुका है। अगस्त 2010 में सोने की कीमत जहां 18,800 रुपए थी, वह अब बढ़कर शुक्रवार को 27,140 रुपये तक पहुंच गई है। इसके पहले जनवरी 2010 में सोने की कीमत 16,600 रुपए प्रति ग्राम थी। ऐसे में जिन ग्राहकों ने करीब एक साल पहले 18,000 रुपये की कीमत के आधार पर गोल्ड लोन लिया है, वह अब कंपनियों के साथ बातचीत कर अतिरिक्त कर्ज बाजार की कीमत के आधार पर ले सकते हैं। हालांकि कंपनियां कीमतों में होने वाले तेजी से बदलाव को देखते हुए मौजूदा कीमत की तुलना में थोड़े कम कीमत पर आपको अतिरिक्त कर्ज दे सकती हैं।

मुत्थूट फिन कार्प लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट सद्दाफ सैय्यद ने बिजनेस भास्कर को बताया कि कंपनी गिरवी रखे सोने की कीमत की तुलना में 70-80 फीसदी तक राशि कर्ज के रूप में देती है। ऐसे में पिछले दिनों में बढ़ी कीमत का लाभ वह अपने ग्राहकों को भी दे रही है। ग्राहक बढ़ी हुई अतिरिक्त कीमत के बदले में मौजूदा ब्याज दर के आधार पर कर्ज ले सकते हैं। हालांकि यह सुविधा उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी, जिनका कर्ज चुकाने के मामले में रिकार्ड अच्छा है।

मुत्थूट फाइनेंस लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंपनी ऐसे ग्राहकों को सोने की बढ़ी हुई कीमत के आधार पर अतिरिक्त कर्ज दे रही है, जिनका कर्ज चुकाने का रिकार्ड अच्छा रहा है। कंपनी इस समय एक फीसदी प्रति माह के आधार पर गोल्ड लोन दे रही है। कंपनी इस समय 80-90 फीसदी तक राशि गिरवी रखे सोने की कीमत के आधार पर दे रही है।

देश में गोल्ड लोन का कारोबार का इस समय 55-60 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। जो कि इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपये का कारोबार है। गोल्ड लोन कारोबार में फाइनेंस कंपनियों के साथ-साथ देश के प्रमुख बैंक भी अब इस कारोबार को तेजी से बढ़ा रहे हैं।